and expenditure have shown steady increase over the past three years.

(b) Does not arise.

(c) Super Bazar has reported that efforts are being made to increase turnover. No fresh recruitment of employees is being made. These measures are being taken to increase per capita sale and net profit.

(d) No specific amount has been earmarked for this purpose by Super Bazar.

Deposit by RPFC, Delhi

2105. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is true that the organisations under the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi have to deposit huge amount with the authorities in respect of both the contributions;

(b) if so, what are the details of outstanding, amounts office-wise, under RPFC Delhi;

(c) whether it has also come to the notice of the Ministry that with the connivance of the officials of the office of the Provident Fund Commissioners, the organisations are violating the norms and rules of the PF Act; and

(d) if so, what action has been taken against such erring officials?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Beedi Industry in Uttar Pradesh

2106. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that laws pertaining to beedi industry are not being enforced strictly in Uttar Pradesh which is under President's Rule;

(b) if so, the steps taken to ensure enforcement of the laws in that industry; and

(c) the step taken to weed out corrupt officers entrusted with the responsibility of enforcing these laws?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No such report has come to the notice of the Government.

(b) and (c) Does not arise.

सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मंद कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतें

2107. **श्री मोहम्मद मसूद खान:**
श्री रामदेव भंडारी:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की गति बहुत धीमी होने के बारे में सांसदों को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने धीमी प्रगति के कारणों का पता लगाया है;

(ग) क्या सरकार इन योजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिला स्तर पर विशेष "सेल" स्थापित करेगी,

(घ) सरकार इस योजना को तीव्र गति से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(ङ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन की धीमी गति के संबंध में कुछ सांसदों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी हां,

(ग) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिए जिला स्तर पर संबंधित जिले का जिला कलेक्टर समन्वय तथा समग्र पर्यवेक्षण के लिए, जिम्मेदार है। जिला कलेक्टर स्वयं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कार्यान्वयन एजेंसियों तथा